



सामयिक बाजारों (हाट) का सामाजिक-आर्थिक विकास तथा विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान (इटावा जनपद के सन्दर्भ में एक भौगोलिक अध्ययन)

डा० धीरेन्द्र सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
भूगोल विभाग

मन्मूलाल द्विवेदी महाविद्यालय, सहार, औरैया (उ०प्र०)

मो० नं० 9457278660, 9675458123

प्रस्तावना—

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य का पाने में सामयिक बाजारों (हाट) की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बाजार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने और कृषि-आधारित लघु उद्योगों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। ये बाजार ग्रामीण आय बढ़ाने स्थानीय रोजगार पैदा करने और सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों को मजबूती देने के केन्द्र हैं। सामयिक बाजार ग्रामीण-शहरी विकास की खाई को कम करने तथा आत्म निर्भर भारत के विजन को साकार करने में एक स्थानीय रीढ़ की तरह कार्य करते हैं।

सामयिक बाजारों की अर्थव्यवस्था अति-प्राचीन है तथा इनका स्वरूप समयानुसार उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तित होता रहा है। वर्तमान में इनका झुकाव आधुनिकीकरण की ओर है, परन्तु इन पर प्राचीन व्यवस्था की छाप किसी न किसी रूप में आज भी विद्यमान है। अतः यह कहना सही होगा कि इन सामयिक बाजारों की व्यवस्था अपने वर्तमान स्वरूप में प्राचीन-आधुनिक का मिश्रण है। स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का इनके निरूपण में काफी हद तक योगदान रहता है जिसका स्पष्ट उदाहरण यहां क्रय-विक्रय के लिए लायी जाने वाली वस्तुओं, जो समीपवर्ती भौगोलिक दूरी के अनुरूप उपजाई एवं बनायी जाती है, से देखने को मिलता है। ऐसा देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपनी आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये तथा अपनी कृषि उपजों एवं बनायी गयी वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिए इन्हीं सामयिक बाजारों पर अधिक निर्भर करते हैं।

सामयिक बाजारों को 'आवधिक' या 'आवर्ती' बाजारों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाजार सप्ताह के प्रत्येक दिनों में न लगकर सप्ताह के एक, दो या तीन दिवसों में लगते हैं। बाजारों के मध्य दिनों के इस अन्तराल के कारण इन्हें सामयिक या आवर्ती बाजार के नाम से जाना जाता है। इन्हें स्थानीय भाषा में 'हाट' या 'पैठ' के नाम से भी जाना जाता है। मार्क 1931 के शब्दों में "विपणन केन्द्र स्थल अपने चतुर्दिक ग्रामीण क्षेत्रों के बहुविध क्रियाकलापों को सम्पादित करते हैं।" होडर (1971) महोदय के शब्दों में विपणन केन्द्र के मूल्यांकन एवं सीमांकन तथा वितरण की उस श्रृंखला से सम्बन्धित



हैं जिनके द्वारा वस्तुएं उत्पादनकर्ता तथा उपभोगकर्ता के मध्य प्रवाहित होती हैं।" ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के जीवन में इन बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्रियाकलापों पर अधिक आधारित है। सीमित आर्थिक साधन, न्यून क्रय शक्ति तथा परम्परागत सादा एवं संतोषप्रद जीवन व्यवस्था के कारण दैनिक बाजारों का परिपोषण सुगमता से नहीं हो पाता है। फलतः ग्रामीण जनमानस इन्हीं बाजारों पर निर्भर है।

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि शोध अध्ययन का उद्देश्य—

1. सामयिक बाजारों का विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में भूमिका का आंकलन करना।
2. सामयिक बाजारों का सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान का आंकलन एवं परीक्षण करना।

शोध विधितंत्र एवं सूचना स्रोत—

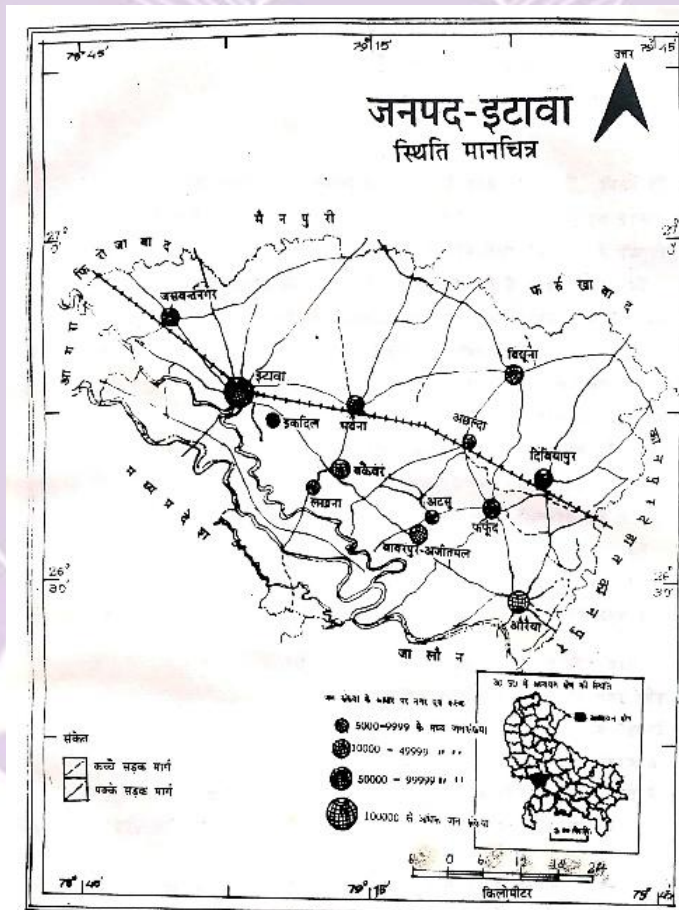
प्रस्तुत शोध पत्र इटावा जनपद में लगने वाले 111 सामयिक बाजारों से एकत्रित प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन शोधार्थी द्वारा स्वयं बाजार केन्द्रों का सर्वेक्षण कर क्रेताओं एवं विक्रेताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर किया गया है तथा द्वितीयक आंकड़े जनगणना निदेशालय से प्राप्त किये गये हैं। भूमि उपयोग, कृषि एवं आर्थिक क्रियाकलापों सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन इटावा जनपद के राजस्व विभाग से प्राप्त किये गये हैं। सामयिक बाजारों के आंकड़ें अध्ययन क्षेत्र से प्राप्त किये गये हैं। प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़े प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है।

अध्ययन क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि—

इटावा जनपद (17 सितम्बर 1997 को इसकी दो तहसीलों औरैया एवं बिधूना को पृथक कर औरैया जनपद बनाया गया है प्रस्तुत शोध अध्ययन वर्तमान समय में दोनों जनपदों में अध्ययन के आंकड़ों पर आधारित है।) उत्तर प्रदेश में कानपुर मण्डल के अन्तर्गत निम्न गंगा-यमुना दोआब के ऊपरी भाग में 4326 वर्ग किमी⁰ क्षेत्र में विस्तृत (मानचित्र-1) है। यह 26°27' से 27°1' उत्तरी अक्षांश एवं 78°45' से 79° 45' पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला हुआ है। दोआब में अव्यवस्थित होने के कारण अधिकांश भाग समतल है, लेकिन यमुना के निकट का भाग बीहड़ों एवं खारों से घिरा हुआ है। (राजपूत 1993) मानसूनी प्रदेश में अवस्थित होने पर भी यहाँ की जलवायु अर्द्धशुष्क के सन्निकट है। (राजपूत 1993) जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के केवल 9.3 प्रतिशत भाग पर वन विस्तृत है जबकि कृषित भूमि का प्रतिशत (73.7) सर्वाधिक है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है क्योंकि इस अवखण्ड में कुल

कृषिगत जनसंख्या का प्रतिशत 77 है। द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों में लगे लोगों का प्रतिशत क्रमशः 4.49 एवं 18.51 है।

कृषि के दृष्टिकोण से सम्पन्न एवं गंगा के उपजाऊ मैदान में अवस्थित होने के कारण जनपद में अवसंरचना सम्बन्धी सुविधायें पर्याप्त है, जिनका प्रभाव सामयिक बाजार केन्द्र स्थलों पर पड़ता है। विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत 64.3 है, जिससे आर्थिक प्रगति कम हो सकी है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण चौपायों का घनत्व 247 किमी²0 (1988 पशुगणना के अनुसार) है। चौपायों पर पशुपालन उद्योग ही नहीं, विकसित हुआ है बल्कि इन पर पशु बाजारों का व्यवसाय भी निर्भर रहता है। यहाँ की कुल 2124655 जनसंख्या (1991) यहाँ के 1462 ग्रामों में निवास करती है तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 84.29 है। कृषि प्रधान जनपद होने के कारण जनसंख्या का घनत्व 489.06 किमी²0 से अधिक है, लेकिन साक्षरता का प्रतिशत 78.68 है। साक्षरता भी क्रय-विक्रय पर अपना प्रभाव छोड़ती है।



मानचित्र-01

इटावा जनपद के सामयिक बाजार:-

इटावा जनपद की भौगोलिक पृष्ठभूमि में ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता के कारण यहां दैनिक बाजारों की अपेक्षाकृत सामयिक बाजारों का ही अधिक परिपोषण हुआ है। (सिंह-1997) अध्ययन क्षेत्र के सामयिक बाजारों को निम्नलिखित तालिका एवं मानचित्र-02 से जाना जा सकता है-

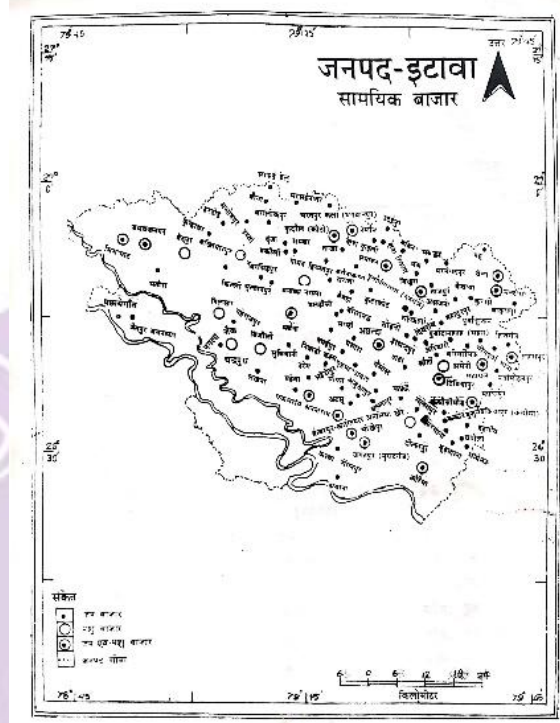
तालिका-01

जनपद इटावा: ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले
सामयिक बाजार वर्ष 1961-91

वर्ष	ग्रामीण सामयिक बाजार	नगरीय सामयिक बाजार	कुल सामयिक बाजार
1961	65	6	71
1971	76	9	85
1981	90	11	101
1991	100	11	111

स्रोत:- उत्तर प्रदेश जिला जनगणना हस्तपुस्तिका- 1961, 1971, 1981 तथा क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर।

उपरोक्त तालिका 01 से ज्ञात होता है कि इटावा जनपद में वर्ष 1961 में कुल 71 सामयिक बाजार लगते थे जिसमें से 65 बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 6 बाजार नगरीय एवं कस्बाई क्षेत्रों में लगते थे। वर्ष 1971 तथा 1981 में सामयिक बाजारों की संख्या बढ़कर क्रमशः 85 तथा 101 बाजार हो गयी। वर्ष 1991 में जनपद में 111 सामयिक बाजार लगते हैं जिसमें से 100 बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 11 बाजार नगरीय एवं कस्बाई क्षेत्रों में लगते हैं। सामयिक बाजारों का सामाजिक-आर्थिक विकास तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान का आंकलन एवं परीक्षण में इन्हीं बाजार केन्द्रों से एकत्रित आंकड़ों का आधार लिया गया है।



मानचित्र-02

सामयिक बाजारों का सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान- इटावा जनपद में लगने वाले कुल-111 सामयिक बाजारों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ये बाजार ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास की रीढ़ है जो स्थानीय उत्पादकों, खरीददारों और विक्रेताओं को जोड़ते हैं। ये बाजार आजीविका रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाजार उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने और उपभोक्ताओं को सीधे उत्पाद प्राप्त करने में मदद करते हैं। इटावा जनपद के शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये बाजार निम्न प्रकार से सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देते हैं-

1. ये बाजार स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ये बाजार छोटे उत्पादकों और विक्रेताओं को क्रय-विक्रय का एक मंच प्रदान करते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश विक्रेता स्वयं में उपभोक्ता भी होते हैं और आवश्यकता पूर्ति के लिए इन बाजारों पर निर्भर हैं। ये बाजार विक्रेताओं की आय वृद्धि में सहायक होते हैं।
2. ये बाजार ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के अवसर प्रदान कर ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं।
3. ये बाजार ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी या साप्ताहिक रोजगार के अवसर (विशेषकर असंगठित क्षेत्रों के लिए) प्रदान करते हैं।

4. ये बाजार किसानों एवं कारीगरों तथा लघु उद्यमियों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्रदान करवाने में सहायक है।
5. ये बाजार ग्रामीणों की आधारभूत दैनिक आवश्यकताओं (जैसे-षाक-सब्जी, कपड़े, उपकरण आदि) की आपूर्ति का सुलभ साधन है जो स्थानीय स्तर के साथ-साथ दूरस्थ क्षेत्रों तक अपनी पहुंच रखते हैं।
6. जनपद की मिश्रित कृषि अर्थव्यवस्था के कारण पशुपालन का व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय के रूप में क्रियाशील है। इससे जहां डेयरी उद्योग से ग्रामीणों को आय प्राप्त हो रही है वहीं पशुओं के क्रय विक्रय से ही लाभ प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार यह बाजार केन्द्र पशुओं के क्रय विक्रय में रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक है।
7. ये बाजार स्थानीय उत्पादों के क्रय-विक्रय के माध्यम से ग्रामीण पुरुषों एवं महिलाओं को सशक्त बनाकर उनको आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।
8. ये सामयिक बाजार केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों का साधन उपलब्ध कराकर, रोजगार के अवसर प्रदान कर तथा क्षेत्रीय विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर (सिंह धीरेन्द्र-2001) ग्रामीणों का शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने में सहायक हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि इटावा जनपद के सामयिक बाजार न केवल इटावा जनपद के ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक है, अपितु इसी प्रकार की सामयिक बाजारों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाले अन्य राज्यों एवं राष्ट्र के ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक स्तर के उन्नयन में सहायक होंगे।

सामयिक बाजारों का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान—

वर्तमान समय में भारत सरकार का लक्ष्य भारत देश को वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तथा अर्थव्यवस्था 30 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाना है। सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बाजार अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शोधार्थी द्वारा इटावा जनपद के शोध अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विप्लेषण से यह निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये सामयिक बाजार निम्न रूपों में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं—

1. ये बाजार ग्रामीण कृषकों, कारीगरों तथा लघु एवं सीमान्त उद्यमियों को उनकी उपज या उत्पादन का सही मूल्य प्रदान करवाकर उनकी आय में वृद्धि कराने में सहायक है।
2. ये बाजार ग्रामीण स्तर पर किसानों एवं कारीगरों को बिचौलियों के बिना अपने उत्पाद को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान कर ग्रामीणों की आय वृद्धि में सहायक हैं।

3. ये बाजार स्थानीय स्तर पर क्रय-विक्रय की प्रक्रिया एवं व्यापार को सरल बनाते हैं जिससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मजबूती मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित होते हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है।
4. वे सामयिक बाजार ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकता पूर्ति में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिससे एक आत्म निर्भर ग्रामीण पारिस्थितिक तंत्र का विकास होता है।

रणनीति—

सामयिक बाजारों से सम्बन्धित (क्रेताओं एवं विक्रेताओं) की समस्याओं का निराकरण निम्न प्रकार से किया जाना आवश्यक है—

1. बाजारीय स्थलों में स्वच्छता बनाये रखने हेतु बाजार लगने से पूर्व बाजारीय स्थलों की साफ-सफाई की जानी चाहिए। कूड़ा-करकट के निपटान हेतु स्थलों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा बाजारीय स्थलों में कूड़ेदान स्थापित किये जाने चाहिए।
2. बाजारीय स्थलों में पर्याप्त स्थान की समस्या के निराकरण के लिए जो बाजार सड़क मार्गों के किनारे लगते हैं उनके स्थलों की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि बाजारीय दिवस के दिन सड़क पर जाम न लगे।
3. क्रेताओं एवं विक्रेताओं के पेयजल की समस्या के निराकरण के लिए बाजार स्थलों में जगह-जगह प्याऊ लगाये जायें तथा विक्रेताओं को उनके स्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी जाय।
4. बाजारीय स्थल में चबूतरो एवं गलियों से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु पक्की गलियों तथा चबूतरों का निर्माण किया जाय।
5. बाजारीय स्थलों में सक्रिय विचौलियों के कारण क्रेताओं एवं विक्रेताओं को होने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विचौलियों के हस्तक्षेप को प्रतिवन्धित किया जाना चाहिए ताकि क्रेताओं एवं विक्रेताओं का उचित मूल्य एवं लाभ प्राप्त हो सके। जेवकतरों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
6. बाजार केन्द्रों में वस्तुओं के क्रय-विक्रय पर ली जाने वाली अधिक तहबजारी पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।
7. बाजारीय व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिम्मेदार व्यवस्थापक समितियों के न होने तथा धनाभाव होने के कारण बाजारीय व्यवस्थाओं का संचालन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। अतः बाजारीय स्थल में जिम्मेदार समितियों का गठन किया जाना चाहिए तथा बाजारीय स्थल के अवसंरचनात्मक विकास हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था शासन प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

निष्कर्ष—

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी आंकड़ों के विप्लेषण एवं परीक्षण के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यद्यपि ये ग्रामीण सामयिक बाजार प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में सहायक हैं तथा भारत सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य-2047 को प्राप्त कराने में भी सहायक हैं तथापि इन बाजारों की जितनी अधिक सक्रिय भूमिका सामाजिक-आर्थिक स्तर के उन्नयन एवं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कराने में होनी चाहिए उतनी इन बाजार केन्द्रों से सम्बन्धित उपभोक्ताओं एवं विक्रेताओं को होने वाली समस्याओं का निराकरण न हो पाने के कारण अदा नहीं हो पा रही है। यदि ग्रामीण स्तर के इन सामयिक बाजारों पर निर्भर ग्रामीणों (क्रेताओं एवं विक्रेताओं) की समस्याओं का निराकरण स्थानीय बाजारीय संगठनों के प्रशासकों, नियोजकों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं शासकों द्वारा योजना बनाकर इनका निराकरण कर दिया जाये तो ये बाजार ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक स्तर के और अधिक उठाने तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को सुगम बनाने में सहायक होंगे।

सन्दर्भ सूची—

- 1- Hodder, B.W. (1971) Periodic And daily Markets in West Africa in C. Meillasum (Ed.) Development of Indigenous, Trade and Markets in West Africa, London. Oxford University Press. Vol.3, PP.347-358.
- 2- Mark, J (1931) The Distribution of the World's City Folks: A Study in Comparative Civilization, Geographical Review, Vol. 21, P-453.
3. प्रसाद, यदुनन्दन (2004) आजमगढ़ जनपद के आवर्ती विपणन केन्द्रों का भू-वैचारिक प्रतिरूप, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, अंक 40, जून-दिस0 गोरखपुर, पृष्ठ-21.
4. राजपूत, प्रेम प्रकाश एवं श्रीवास्तव रमेश चन्द्र (1993) ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन उपभोग: पर्यावरण प्रदूषण एवं स्वास्थ्य संकट : इटावा जनपद का एक प्रतीक अध्ययन, उत्तर भारत भूगोल पत्रिका अंक 29, संख्या 1-2, जून-दिस0 गोरखपुर पृष्ठ-142.



5. सिंह, धीरेन्द्र (1997) इटावा जनपद के सामयिक बाजार एवं उपभोक्ता व्यवहार का भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित षोधग्रन्थ डा0 भीमराव अम्बेडकर विष्णुविद्यालय, आगरा पृष्ठ-2.
6. Dixit Rs (1984 Market Centres and Their Spatial Development in the Umland of Kanpur, Kitab Mahal, Allahabad.
7. सिंह धीरेन्द्र (2001) क्षेत्रीय विकास में सामयिक बाजारों की भूमिका (उ0प्र0 के कानपुर देहात जनपद के रसूलाबाद तहसील के सन्दर्भ में, आई0सी0एस0एस0आर0 की शोध परियोजना.
8. Sanjeev Kumar (2003) Planning for Socio-Economic Development of Karhal Tehsil, A Microlevel Geographical study A unpublished Ph.D Thesis, Dr. B.R.A. University Agra.
9. Sujata Mishra, 2003 A Geo-Economic survey of Village Maisadali, A Research Paper Published in Geographical review of India, vol 65, Number1, March 2003, PP-93-97.